नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

# नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 067
दि. 09.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com


# नागपुर में गूँजी चार दिशाओं की हुंकार; शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सड़क पर उतरी जनशक्ति, सरकार को कड़े चेतावनी-संदेश

**(जीएनएस)**। महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन नागपुर में ऐसा बीता, मानो विधानभवन नहीं बल्कि आंदोलनकारियों का विशाल चौक हो। शहर की प्रमुख सड़कें सुबह से ही नारेबाजी, ढोल-ताशों, बैनरों और मांगों की गूंज के बीच थर्रा उठीं। “अधिकार दो, न्याय दो”, “सम्मान चाहिए, कृपा नहीं” और “हमारा हक़ लौटाओ” जैसे गगनभेदी नारे विधानसभा भवन के दायरे से बहुत दूर तक फैलते चले गए। नागपुर में एक साथ चार बड़े मोर्चे निकलने से प्रशासन की सांसें थमी रहीं और सत्र की शुरुआत ही तनावपूर्ण माहौल में हुई।

यशवंत स्टेडियम, मॉरिस कॉलेज टी-पॉइंट, विधानभवन मार्ग और सुभाष रोड के आसपास हजारों लोग अलग-अलग मुद्दों को लेकर एक ही सुर में अपनी आवाज़ बुलंद करते दिखे। विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर विकास मंच, युवा शैक्षणिक एवं सामाजिक न्याय संगठन और डिंडोरा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समिति—ये चारों मोर्चे अलग-अलग मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हुए भी एक साझा संदेश दे रहे थे कि जनता अब मौन नहीं रहना चाहती। उनके हाथों में तख्तियां थीं, जिन पर लिखा था—“न्याय मिलेगा तो ही विकास होगा”, “नीतियां नहीं बदलीं तो सरकार बदलेगी”, और “अधिकार की लड़ाई सड़क से सदन तक”। इन नारों ने नागपुर की सड़कों को मानो किसी लोकतांत्रिक महाधरना स्थल में बदल दिया।

सबसे अधिक तीखी आवाज़ उस समूह से आई, जो चंद्रपुर जिले की बहुचर्चित डिंडोरा परियोजना से प्रभावित था। लोगों का आरोप था कि 477 करोड़ की लागत से शुरू हुई परियोजना का खर्च बढ़ते-बढ़ते 1,600 करोड़ रुपये तक पहुँच गया, लेकिन विस्थापितों का मुआवज़ा आज भी सिर्फ 58 करोड़ रुपये पर अटका हुआ है। उनका कहना था कि जिस जमीन पर उनकी पीढ़ियाँ पली-बढ़ी, जिसकी मिट्टी ने उन्हें पहचान दी, उसकी कीमत इतनी कम लगाना बेहद अपमानजनक है। आंदोलनकारियों के चेहरे पर गुस्सा और आंखों में अपनी जमीन खोने का दर्द दोनों साफ दिख रहा था। वे लगातार सरकार पर यह आरोप दोहराते रहे कि विकास परियोजनाओं के नाम पर जनता को कुचला जा रहा है और मुआवज़े का इंतज़ार करते-करते कई परिवार कर्ज में डूब चुके हैं।

इसी भीड़ में युवा शैक्षणिक एवं सामाजिक न्याय संगठन का विशाल जत्था शिक्षा व्यवस्था में गहराई तक बैठे अव्यवस्थाओं को लेकर नारे लगा रहा था। संगठन के अध्यक्ष संदीप कांबले के नेतृत्व में जुटे प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राज्य में जिला परिषद स्कूलों की हालत लगातार खराब होती जा रही है और सरकार संविदा आधारित भर्ती को बढ़ावा देकर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका आरोप था कि पवित्र पोर्टल के माध्यम से भर्ती की प्रणाली में कला शिक्षक, खेल शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक और कार्य-अनुभव वाले प्रशिक्षकों की उपेक्षा की जाती है। कई शिक्षकों ने बताया कि अस्थायी नियुक्तियां उन्हें असुरक्षित बनाती हैं, और भविष्य की कोई गारंटी नहीं देती। उनका कहना था कि अगर 100 प्रतिशत नियमित भर्ती लागू न हुई तो जिले के 20 से ज्यादा स्कूल बंद होने की कगार पर आ जाएंगे।

विदर्भ विकलांग संघर्ष समिति का मार्च तो कुछ देर के लिए इतना उग्र हो गया कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई। बैरिकेड हटाने की कोशिश में माहौल गड़बड़ा गया और प्रशासन को तत्काल अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। समिति की मुख्य मांग थी कि संजय गांधी निराधार योजना की राशि को 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए और दिव्यांग नागरिकों को राज्य भर में समान सुविधाएं प्रदान की जाएं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि योजनाएँ तो वर्षों से चल रही हैं, लेकिन लाभार्थियों की संख्या बढ़ने के बावजूद बजट वहीं का वहीं अटका हुआ है।

चारों आंदोलनों के कारण विधानभवन परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी और पुलिसकर्मियों को कई जगह मोर्चा संभालना पड़ा। विधानसभा के पहले दिन ही इतना भारी जनदबाव देखकर स्पष्ट हो गया कि आने वाले दिनों में सत्र विपक्ष और जनता दोनों के दबाव का सामना करेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर संगठित विरोध बताता है कि जनता अब सिर्फ आश्वासनों से संतुष्ट नहीं है।

सभी संगठनों ने सरकार को एक ही चेतावनी दी—अगर जनता की आवाज़ दबाई गई या मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो संघर्ष आगे और तेज होगा। नागपुर में छलका यह जनरोष आने वाले दिनों में राजनीति को किस दिशा में मोड़ेगा, यह सत्र खत्म होने तक साफ हो जाएगा।

# वंदे मातरम का राष्ट्रगीत बनना: कांग्रेस की पहल और देशभक्ति की प्रेरणा

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। लोकसभा में वंदे मातरम् पर रविवार को हुई विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि वंदे मातरम् को राष्ट्रगीत का दर्जा दिलाने की पहल कांग्रेस ने ही की थी। उन्होंने सदन में भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की आज़ादी और राष्ट्रनिर्माण में पंडित नेहरू सहित कांग्रेस के योगदान को कोई कम नहीं कर सकता।

गोगोई ने सदस्यों को बताया कि वंदे मातरम् को पहली बार 1905 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में अपनाया और निर्णय लिया कि हर कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत इस गीत के उद्घोष से की जाएगी। इस कदम ने इसे देशव्यापी लोकप्रियता दिलाई और स्वतंत्रता संग्राम में इसका महत्व बढ़ाया। उन्होंने याद दिलाया कि इस गीत का विरोध उस समय मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने किया था, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्पष्ट कहा था कि उन्हें इस गीत से कोई आपत्ति नहीं है।

सदन में चर्चा के दौरान गोगोई ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सरला देवी चौधरानी को भी याद किया। बंकिम चंद्र ने इस गीत को बंगाल की पृष्ठभूमि पर लिखा, जबकि सरला देवी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय वंदे मातरम् जनता को एकजुट करने का सबसे प्रभावी प्रतीक बनकर उभरा। रवींद्रनाथ टैगोर, खुदीराम बोस और अनेक स्वतंत्रता सेनानी इस गीत की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में आगे आए।

गोगोई ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने सदन को बताया कि इस गीत की 150वीं वर्षगांठ पर इसे याद करना न केवल इतिहास का सम्मान है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और एकजुटता की भावना से जोड़ने का अवसर भी है। गोगोई ने जोर देकर कहा कि हर नागरिक का दायित्व है कि वह इस गीत की भावना—एकजुट भारत—को सही मायने में समझे और निभाए।

सदन में उन्होंने स्पष्ट किया कि वंदे मातरम् का महत्व राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है और इसे राष्ट्र की एकता और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि यह गीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसे सिर्फ सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वर्तमान समय में भी एकजुटता और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए याद रखा जाना चाहिए।

# बीजापुर में नक्सलियों ने किया सड़क परियोजना ठेकेदार की हत्या, क्षेत्र में तनाव बढ़ा

**(जीएनएस)**। बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में रविवार की देर शाम एक भयावह घटना ने इलाके की जनता को दहला दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम कर रहे ठेकेदार इम्तियाज अली को नक्सलियों ने अपहरण करने के बाद निर्ममता से हत्या कर दी। घटना पामेड़ थाना क्षेत्र के मेटागुड़म गांव की है, जहां ठेकेदार अपने कर्मचारियों के साथ सड़क निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे थे। स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार, नक्सलियों ने इम्तियाज और उनके एक सहयोगी को अपने कब्जे में ले लिया। अपहृत सहयोगी किसी तरह नक्सलियों के चंगुल से बचकर मेटागुड़म सुरक्षा कैंप पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी पुलिस और सुरक्षा बलों को दी। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें रवाना हुईं, लेकिन तब तक ठेकेदार की हत्या कर दी गई थी। नक्सलियों ने शव को रास्ते में फेंक दिया और पामेड़ एरिया कमेटी ने घटना की जिम्मेदारी लेने वाला पर्चा वहीं छोड़ दिया।

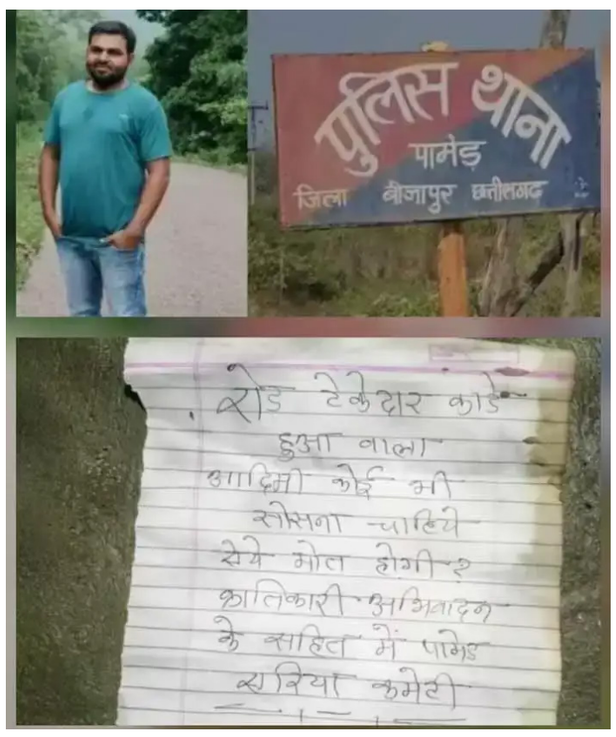


बीजापुर के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने पुष्टि की कि ठेकेदार का अपहरण और हत्या की गई है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है और नक्सलियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस का मानना है कि नक्सली इस तरह की घटनाओं के जरिए विकास परियोजनाओं में बाधा डालना और सुरक्षा बलों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करना चाहते हैं। घटना ने जिले में भय का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय ग्रामीणों और निर्माण कार्य से जुड़े कर्मचारियों का कहना है कि इम्तियाज अली अपने काम में ईमानदार और समय पर कार्य पूरा करने वाले ठेकेदार थे। उनकी हत्या से न केवल विकास कार्य प्रभावित होंगे, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की चुनौती और बढ़ गई है।

पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके में अतिरिक्त पेट्रोलिंग और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नक्सलियों को दबाने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस घटना ने राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के सामने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती को फिर से उजागर किया है। साथ ही, यह भी संकेत दिया है कि नक्सलियों की सक्रियता अभी भी गंभीर खतरा बनी हुई है, जिससे ग्रामीण और निर्माण कार्य प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

# बेंगलुरु में C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए नया एमआरओ सेंटर: टाटा और लॉकहीड मार्टिन ने किया उद्घाटन

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और लॉकहीड मार्टिन ने सोमवार को बेंगलुरु में घोषणा की कि भारत में ही C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट के लिए डिफेंस मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधा स्थापित की जाएगी। इस नए आधुनिक सेंटर का निर्माण 2026 के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है और 2027 की शुरुआत में पहला एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए उपलब्ध होगा।

भूमि पूजन समारोह में वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। लॉकहीड मार्टिन के सीओओ फ्रैंक सेंट जॉन ने कहा कि भारत के एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के साथ उनकी साझेदारी अब और मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि यह एमआरओ सेंटर न केवल भारतीय वायु सेना की तैयारी को बेहतर बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सी-130 ऑपरेटर्स के लिए भी सहयोग और समर्थन के नए अवसर खोलेगा।

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के सीईओ सुकरण सिंह ने बताया कि सेंटर में डिपो-लेवल मेंटेनेंस, भारी मरम्मत, कंपोनेंट रिपेयर, ओवरहॉल, टेस्टिंग, एवियोनिक्स अपग्रेड और संरचनात्मक बहाली जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा भारतीय इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं भी इस सेंटर में दी जाएंगी, जिससे देश के एयरोस्पेस इकोसिस्टम को और मजबूती मिलेगी और तकनीकी कौशल में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

लॉकहीड मार्टिन एयर मोबिलिटी के उपाध्यक्ष रॉड मैकलीन ने कहा कि यह कदम भारत-अमेरिका रक्षा सहयोग और दशकों पुराने निवेश की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में नए एमआरओ सेंटर में C-130J सुपर हरक्यूलिस, KC-130J और C-130 B-H एयरक्राफ्ट की मरम्मत और रखरखाव कार्य किए जाएंगे।

मैकलीन ने यह भी उल्लेख किया कि C-130 सुपर हरक्यूलिस ने दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे दौलत बेग ओल्डी पर लैंडिंग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया और पूर्वी लद्दाख के न्योमा एयरबेस पर उतरकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि नया एमआरओ सेंटर भारत में C-130 प्लेटफॉर्म और देश के बीच दीर्घकालीन साझेदारी की नींव रखेगा और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को और मजबूती देगा।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस पहल से भारत न केवल अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट की मरम्मत में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर C-130 ऑपरेटर नेटवर्क में शामिल होकर रणनीतिक महत्व भी बढ़ाएगा। यह सेंटर भारतीय वायु सेना की तत्परता, सुरक्षा क्षमता और एयरोस्पेस तकनीकी कौशल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

बेंगलुरु में स्थापित इस एमआरओ सेंटर से भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित कर्मियों और उन्नत तकनीकी संसाधनों का लाभ मिलेगा, जिससे देश में एयरोस्पेस और डिफेंस उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भी बढ़ेगी।

# गांवों की मिट्टी में बसती है भारत की शक्ति: केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह का किया उद्घाटन

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति उसके गांवों की मिट्टी और कारीगरों के कौशल में निहित है। उन्होंने बताया कि देश की पुरातन कला परंपराओं और हस्तशिल्प विरासत को संरक्षित करना और प्रोत्साहित करना आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है।

इस विशेष सप्ताह का आयोजन भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने, आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने और विशेष रूप से महिला कारीगरों के योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से किया गया है। यह सप्ताह “हैंडमेड भारत” की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मंत्री ने अपने संदेश में सभी नागरिकों से अपील की कि वे इस सप्ताह को हस्तनिर्मित वस्तुओं के सम्मान के रूप में मनाएं और अपनी खरीद में कारीगरों के उत्पादों को प्राथमिकता दें।

गिरिराज सिंह ने कहा कि भारतीय कारीगर सदियों से कला, परंपरा और संस्कृति की अमूल्य धरोहर को जीवित रखे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हस्तशिल्प केवल वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि यह पीढ़ियों से चली आ रही मेहनत, कौशल और विश्वास की कहानी हैं। उन्होंने कहा, “हर हाथ से बनी चीज़ में हमारे इतिहास, संस्कृति और समुदाय की पहचान छिपी है। इन कृतियों को अपनाकर ही हम अपनी संस्कृति और विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं।”

मंत्री ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने कहा कि कारीगरों से खरीदारी करके उनकी रचनात्मकता को पहचान दें और मिलकर इस समृद्ध विरासत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की यह पहल ‘लोकल फॉर वोकल’ मिशन को और मजबूत करेगी। वर्तमान में हस्तशिल्प क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यह लाखों ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को आजीविका प्रदान करता है।

इस अवसर पर मंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह केवल कला और व्यापार का आयोजन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से यह अपेक्षा जताई कि वे अपने आसपास के कारीगरों की कला को बढ़ावा दें और उन्हें वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में सहयोग करें। राष्ट्रीय हस्तशिल्प सप्ताह के दौरान देशभर में विभिन्न कार्यशालाएं, प्रदर्शनी और कारीगर मेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय और पारंपरिक कलाओं को सामने लाया जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस पहल से न केवल कारीगरों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि भारत की हस्तकला और संस्कृति की वैश्विक पहचान भी मजबूत होगी।

## संपादकीय

# हरियाणा-पंजाब में कैदियों का पुनरुत्थान

वस्तुतः जेल की मूल अवधारण, भटके लोगों को सभ्य समाज के अनुरूप ढालने की ही थी। यही मकसद था कि जेल के एकाकी जीवन में रहकर वे समाज के महत्व को समझ सकें और अपने गलतियों पर आत्ममंथन करें। संगीन अपराधों में लिप्त दुर्दांत अपराधियों को समाज से अलग रखने की तार्किकता हो सकती है। सुधार की अवधारण के क्रम में अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की जेलों में खामोशी से बदलाव की सकारात्मक पहल की जा रही है। जेलों में ग्यारह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई की शुरूआत की गई है। यह पहल राष्ट्रीय कौशल विकास मानकों के अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम एनसीवीईटी व एनएसक्यूएफ प्रमाणन के तहत की जा रही है। जिसे कैदियों के जीवन में बड़े बदलाव के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। इसके अंतर्गत ढाई हजार से ज्यादा कैदियों को वेल्डिंग, प्लंबिंग व टेलरिंग आदि व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाना है। निश्चय ही इसे देश की जेलों में महत्वाकांक्षी सुधारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, इस पहल के मूल में यह सोच है कि अपराध में कमी कठोर कारावास से नहीं बल्कि जेल की चाहरदिवारी से बाहर निकलने पर जीवन नये सिरे संवारने लायक बनाने में सहायक आवश्यक साधन प्रदान करने से संभव होगी। कौशल विकास, परामर्श, व्यावहरिक प्रशिक्षण और सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों या एमएसएमई योजनाओं के साथ कैदियों को रिहाई के बाद आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। इसे एक सुरक्षित सामाजिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है।

निश्चित रूप से यदि कोई कैदी प्रमाणित कौशल, सम्मानजनक पेश की संभावना और बदलावकारी भावना के साथ जेल से बाहर आता है, तो उसके फिर से अपराध करने की संभावना उस व्यक्ति के मुकाबले कम होगी, जो असुरक्षित भविष्य व रोजगार के अभाव में फिर से अपराध की गलियों की तरफ मुड़ सकता है। इस सोच को जमीनी रूप से हकीकत में बदलने के लिए उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना होगा, जिनका सामना जेल से बाहर आने पर कैदियों को करना पड़ता है। इसमें जेल से बाहर आने पर कैदियों को अपराध के दाग के रूप में भेदभाव का शिकार होने, उन्हें नियोक्ता द्वारा रोजगार देने में हिचकिचाहट दिखाने, अपर्याप्त नौकरियां जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। निश्चय ही उनके पुनर्वास के लिये व्यावहारिक प्रयासों की जरूरत होगी। इसके साथ ही उद्योग प्रबंधकों को रिहा हुए कैदियों को नौकरी देने के लिये प्रोत्साहित करना होगा। यह बताते हुए कि यह हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है। समाज को भी उनके पुनर्वास को एक सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकारने के लिये संवेदनशील बनाया जाना होगा। निश्चित रूप से हरियाणा व पंजाब नीतिगत दोरोहे पर खड़े हैं। अब देखना है कि वे इस पहल को एक प्रतीकात्मक सुधार के रूप में देखते हैं या वे इसे एक संरचनात्मक परिवर्तन में बदल सकने में कामयाब होते हैं। यदि ऐसा होता है तो वे न्याय को ही पुनर्परिभाषित करेंगे। निस्संदेह, सच्चा सुधारात्मक न्याय कारावास में नहीं, बल्कि भटके हुए नागरिकों को सम्मान, अवसर और आशा के साथ वापस समाज में लाने में निहित है।

# राष्ट्रीय एकता का पुल बनें भारतीय भाषाएं

> आज हमारी सोच बन गई है कि अगर अंग्रेजी में भावानुवाद हो जाए, तो रचना वैश्विक बन जाएगी। लेकिन इस दौड़ में, जहां अंग्रेजी शब्दकोष की सीमाओं के कारण हमारी सांस्कृतिक गरिमा की विविधता खो रही है, वहीं अपने देश के नागरिक भी अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं।

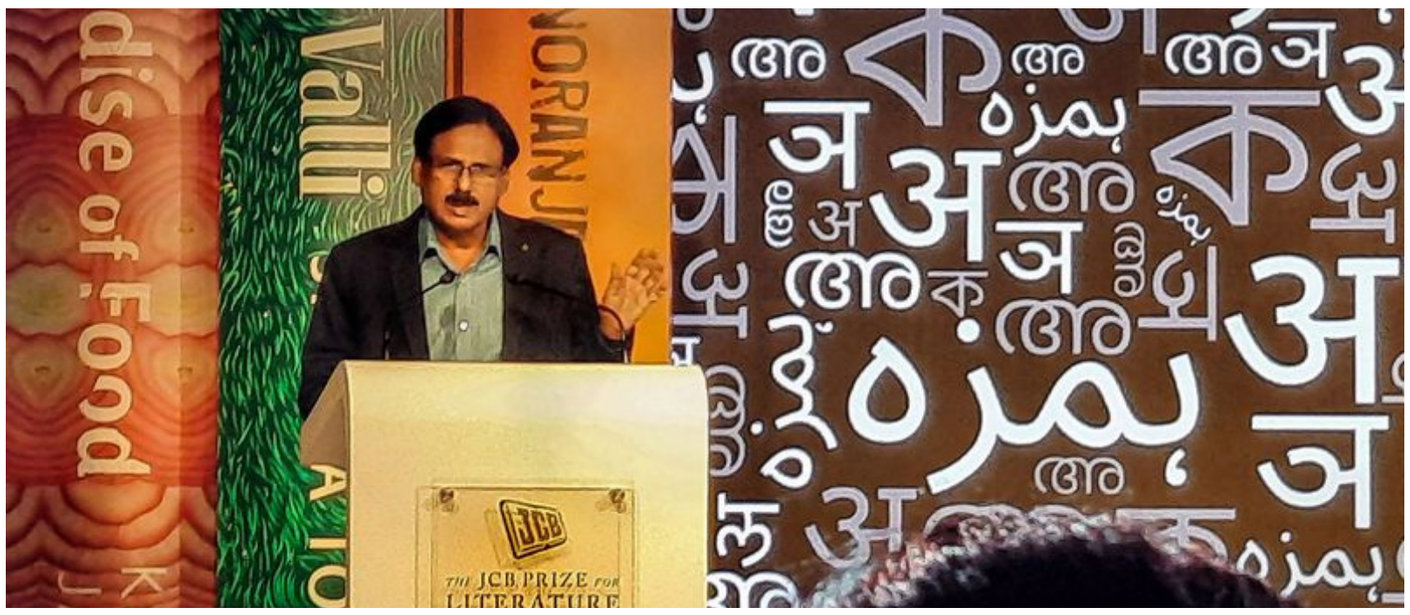


किसी देश की संस्कृति उसकी भाषाओं, साहित्य और परंपराओं से पहचानी जाती है। भारत की भाषाओं की जड़ संस्कृत में है। मध्ययुग की हिंदी और देवनागरी आज देश के अधिकांश लोगों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। लेकिन अंग्रेजों के साम्राज्य ने हमें अंग्रेजी के प्रभाव में डाल दिया, और यह सबसे पहले दक्षिण भारत में प्रभावी हुआ। धीरे-धीरे अंग्रेजी बोलने की क्षमता को ही शिक्षा और समाज में प्रतिष्ठा का पैमाना बना दिया गया। संविधान में हिंदी को 15 वर्ष बाद राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई, लेकिन दक्षिण भारत में इसे स्वीकारने में कठिनाई आई और इसे हिंदी के अधिनायकवाद के रूप में देखा गया। आज भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है, और उसे ही सफलता का पैमाना माना जाता है।

यह कैसी विसंगति है कि हम अपनी भाषा और संस्कृत, जो सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, का न तो सम्मान करते हैं और न ही उसे अपनाने के लिए तैयार हैं। वहीं, जब हिंदी के समर्थन में आवाज उठती है, तो दक्षिण भारत के नेता इसे 'थोपने' के रूप में देखकर इसके प्रति विरोध और राजनीति करते हैं।

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में काशी-तमिल संगमम का आयोजन किया, जिसमें नागरिकों से तमिल भाषा सीखने का आग्रह किया गया। यह चौथा संस्करण है, जिसमें उत्तरी भारत को तमिल अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और तमिल के बीच सांस्कृतिक सामंजस्य स्थापित करना है, जिससे भाषाई कट्टरता को समाप्त किया जा सके और देश में एकता बढ़े।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में भाषाई विरासत के लुप्त होने पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी के पीछे दौड़ते हुए अपनी स्वदेशी भाषाओं, खासकर संस्कृत और मराठी, को भूल रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भगवद्गीता का ज्ञान मराठी में दिया, जिससे समाज को समझाने में आसानी हुई। भागवत ने सवाल उठाया कि हम अपनी हजारों साल पुरानी विरासत की बजाय आधुनिकता के नाम पर अंग्रेजी की ओर क्यों भाग रहे हैं, जबकि हमारे विद्वानों ने संस्कृत में ज्ञान अर्जित किया था। यह आत्मचिंतन का समय है कि हम अपनी संस्कृति और भाषाओं को खोने की ओर क्यों बढ़ रहे हैं।

संस्कृत, जो सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है, आज पश्चिमी देशों में पढ़ाई जा रही है, जबकि हमारे देश में लोग अपनी बुनियादी अभिव्यक्ति के लिए मातृभाषा और अंग्रेजी का मिश्रण करते हैं। अंग्रेजी बोलने का आकर्षण एक तरह से आभिजात्य सोच का प्रतीक बन गया है, जबकि हमारी देसी भाषाओं को पिछड़ेपन का संकेत माना जाता है। यह केवल पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी दास मानसिकता का भी प्रतीक है। अंग्रेजी भाषा के शब्दकोष की सीमितता के बावजूद, हमारी स्वदेशी भाषाएं, जो क्षेत्रीय रूप से समृद्ध हैं, गहरे भावों और विचारों को व्यक्त करने में सक्षम हैं।

अनुवाद और भावानुवाद एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पुल हैं और हिंदी वह मुख्य मार्ग है जो संस्कृत के आधार पर खड़ा है। लेकिन अपनी-अपनी पक्षधरता के कारण और राजनीतिक सीमाओं को स्वीकार करते हुए, हम अपनी स्वदेशी भाषाओं से विमुख हो रहे हैं और अंग्रेजी भाषा की गोद में बैठते जा रहे हैं। एक-एक भाव की अभिव्यक्ति के लिए कई बार हिंदी और संस्कृत के पास जो अनमोल खजाना है, वह अंग्रेजी के पास नहीं है। हम हास्य और शोक जैसे सामान्य भावों को हिंदी और संस्कृत में अनगिनत शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं, जबकि अंग्रेजी के पास उस प्रकार की विविधता नहीं है। हम भारतीय संस्कृति को अंग्रेजी में प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन संस्कृत के कई मूल शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद ही नहीं हो सकता, जैसे 'कल्पवृक्ष'। मोदी जी ने भी अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में इसी पर जोर दिया कि अपनी सोच का विस्तार कीजिए, अपनी सभी भाषाओं को स्वीकार कीजिए। अनुवाद का जहां तक सवाल है, सबसे पहले इन सभी भाषाओं में हमारे ज्ञान और साहित्य की थाती का भावानुवाद होना चाहिए। हम इसके लिए हमेशा अंग्रेजी में अभिव्यक्ति का सहारा न तलाशते रहें।

आज हमारी सोच बन गई है कि अगर अंग्रेजी में भावानुवाद हो जाए, तो रचना वैश्विक बन जाएगी। लेकिन इस दौड़ में, जहां अंग्रेजी शब्दकोष की सीमाओं के कारण हमारी सांस्कृतिक गरिमा की विविधता खो रही है, वहीं अपने देश के नागरिक भी अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। कुछ भारतीय तो मातृभाषाओं को भी नहीं जानते। पहले इन भाषाओं को समझना होगा और इन सामंजस्यपूर्ण पुलों से गुजरना होगा। तभी देश में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो सकेगी और सांस्कृतिक गौरव का अहसास बढ़ेगा। लेकिन जब लोग अपनी-अपनी भाषा के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो कब वे इस सत्य को समझेंगे? यही आज के बदलते युग का सबसे बड़ा सवाल है।

## प्रेरणा

# जब राजकवि ने राजा को असली बुद्धि का दर्पण दिखाया

राजदरबार का विशाल प्रांगण उस दिन विशेष शांति से भरा था। सुबह के सूर्य की किरणें महल के फर्श पर सुनहरे आभा की तरह फैली हुई थीं। सैन्य-सेनापति अपने स्थान पर खड़े थे, दरबारी अपनी–अपनी उपस्थिति को मर्यादित रखते हुए प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज महाराज किस विषय पर विचार करेंगे। इतने में सभा के द्वार धीरे से खुले और राजकवि, जो राज्य के सबसे ज्येष्ठ, ज्ञानी और श्रद्धेय विद्वान माने जाते थे, भीतर प्रवेश करते हैं।

उनके आगमन के साथ ही पूरा दरबार मानो एक अदृश्य सम्मान की तरंग से भर गया। राजा तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया।

"आचार्य, आपका आगमन आज हमारे लिए वरदान के समान है,"

राजा ने गहरी श्रद्धा से कहा।

राजकवि ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया, और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया।

लेकिन उनके शब्दों ने पूरे दरबार को जैसे एक क्षण के लिए स्तब्ध कर दिया—

"महाराज, आपके शत्रु चिरंजीव हों।"

शब्द हवा में तैरते ही राजा के चेहरे का रंग बदल गया।

उनकी भौंहें तन गईं, आँखों में क्रोध की हल्की आग चमकी।

दरबारियों में हल्का-सा कानाफूसी जैसा कंपन उठ गया।

राजा ने स्वयं को संयत करते हुए, पर कठोर स्वर में कहा—

"आचार्य, यह कैसा आशीर्वाद?

मुझे समझ नहीं आता कि आप मेरे शत्रुओं को दीर्घायु होने का आशीष देकर मेरे कल्याण की कैसे बात कर सकते हैं?"

राजकवि शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न चिंता—बस ज्ञान की कोमल चमक थी।

उन्होंने धीरे से कहा—

"महाराज, मैंने आशीर्वाद दिया है, परंतु आपने उसे ग्रहण नहीं किया।"

राजा चौंक उठे।

"ग्रहण कैसे करूँ? आपके शब्द मेरे विरोधियों का भला करते प्रतीत होते हैं!"

राजकवि कुछ कदम आगे आए और अपनी दंडिका पर हाथ टिकाते हुए बोले—

"राजन, इस संसार में दो प्रकार की शक्तियाँ होती हैं—एक जो हमें आगे बढ़ाती है, और एक जो हमें ढीला पड़ने से रोकती है।

आपके मित्र आपको सुख देते हैं,

पर आपके शत्रु आपको सतर्क रखते हैं।

जहाँ मित्र विश्राम देते हैं,

वहीं शत्रु जागृत रखते हैं।

जहाँ मित्र सहज बनाते हैं,

वहीं शत्रु सावधान बनाए रखते हैं।"

उन्होंने आगे कहा—

"अगर आपके शत्रु न रहें, तो क्या होगा?

आप निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे।

आपके सैनिक अभ्यास छोड़ देंगे।

आपकी बुद्धि की धार धीमी हो जाएगी।

आपके रणनीतिक निर्णय दूषित हो जाएंगे।

और सबसे महत्वपूर्ण—आपके भीतर का राजा सोने लगेगा।"

अब राजा की आँखों में क्रोध घट चुका था, और समझ की हल्की चमक दिखाई देने लगी थी।

राजकवि ने और गहरी आवाज़ में कहा—

"आपके शत्रु जीवित रहेंगे, तो आप सतर्क रहेंगे।

आपके शत्रु जीवित रहेंगे, तो आपका पराक्रम जागृत रहेगा।

वे आपके राज्य की सीमा पर खड़े प्रहरी की तरह हैं—

जिनके होने से आप कभी असावधान नहीं होते।

इसलिए मैंने आपके विरोधियों का नहीं,

आपके सामर्थ्य, आपकी बुद्धि, आपकी महिमा और आपकी विजय का आशीर्वाद दिया है।"

पूरा दरबार अब एक अद्भुत मौन में खड़ा था।

राजा के चेहरे पर गंभीरता की रेखाएँ खिल उठीं, जैसे वे अपने भीतर किसी नई रोशनी को महसूस कर रहे हों।

धीरे-धीरे वे अपने सिंहासन से उतरे, राजकवि के समीप आए, और भावुक स्वर में बोले—

"आचार्य, आज आपने मुझे वह बात समझा दी जो वर्षों के युद्ध भी नहीं सिखा सके।

मैंने हर शत्रु को अपने विनाश का कारण माना,

पर आपने बताया कि वे ही मेरी जागरूकता के रक्षक हैं।"

राजकवि ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा—

"महाराज, यही जीवन का सनातन नियम है।

सवेरा तभी पहचाना जाता है जब रात होती है।

जीत तभी मूल्यवान होती है जब संघर्ष होता है।

और राजा तभी महान बनता है जब उसे चुनौती देने वाले जीवित रहते हैं।"

राजा ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा—

"आज से मैं किसी शत्रु को शत्रु नहीं,

बल्कि अपने पराक्रम का पहरेदार समझूँगा।"

उस क्षण से, पूरे राज्य में यह कथा फैल गई—

कि एक दिन राजकवि ने अपने शब्दों से राजा को वह दर्पण दिखाया,

जिसमें उसने अपनी वास्तविक शक्ति पहली बार देखी।

और यही वह क्षण था जिसने एक साधारण राजा को

# एसआईआर पर अनावश्यक आपत्ति, ईवीएम पर संदेह और वोट चोरी के गलत आरोप

भारत का लोकतंत्र विश्व की सबसे विशाल जनइच्छा का प्रतिबिंब है। यहां चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, अपितु एक पवित्र राष्ट्रीय संस्कार है। एक-एक मत स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की धड़कन है। इसलिए मतदाता सूची की शुद्धता केवल भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक आत्मा की सुरक्षा का भी प्रश्न है। इसी मूल भावना के साथ चुनाव आयोग ने इस वर्ष एक जुलाई से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर का व्यापक अभियान आरंभ किया, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति इस सूची में शामिल न हो और कोई पात्र नागरिक छूट न जाए। बिहार के बाद 12 और राज्यों में यह प्रक्रिया जारी है। इससे पहले देश में वर्ष 2002-04 के बीच एसआइआर हुआ था। यह विडंबना है कि कुछ राजनीतिक दल और उनके शीर्ष नेता संविधान की प्रतियां लहराकर स्वयं को उसका 'रक्षक' साबित करने पर तुले रहते हैं, वही संसद के भीतर और बाहर इस वैधानिक चुनाव सुधार प्रक्रिया पर अनर्गल सवाल भी खड़े कर रहे हैं।

देशव्यापी एसआइआर के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में भी मामले दायर हो गए हैं। विपक्षी दलों की ओर से इन मामलों की पैरवी कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज कर रहे हैं। उनकी दलील है कि एसआइआर एक गैर-जरूरी प्रक्रिया है और चुनाव आयोग के पास इसे कराने का अधिकार नहीं है। उनकी इस दलील को अदालत ने खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, न्यायालय ने 26 नवंबर की सुनवाई में यह भी रेखांकित किया कि बिहार में एसआइआर के दौरान जिन अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनमें से किसी एक ने भी कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। अब चुनाव आयोग एसआइआर के दूसरे चरण में 12 राज्यों के 321 जिलों में 1,843 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 51 करोड़ मतदाताओं की समीक्षा कर रहा है।

तीन दिसंबर तक इसके लिए 99 प्रतिशत फार्म वितरित और 93 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइज किए जा चुके हैं। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आयोग अब तक 4,700 से अधिक सर्वदलीय बैठकों का आयोजन कर चुका है। इनमें 28,000 राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अंतिम मतदाता सूची आगामी 16 फरवरी को प्रकाशित होगी। जिन लोगों के नाम सूची से हटेंगे, उन्हें एक माह तक दावा-आपत्ति का अवसर मिलेगा। आखिर इतनी पारदर्शी प्रक्रिया से घबराहट कैसी? विरोधियों द्वारा पहले ईवीएम पर संदेह जताना, वोट चोरी का आरोप मढ़ना और अब एसआइआर का विरोध करना असल में और कुछ नहीं, बल्कि 'नाच न जाने, आंगन टेढ़ा' वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है।

लोकसभा चुनाव में मामूली सफलता के बाद से ही कांग्रेस को एक के बाद एक राज्यों में मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस का यह क्षरण बिहार चुनाव तक कायम रहा, मगर वह आत्ममंथन के बजाय आरोप-प्रत्यारोप में लगी है। स्वतंत्रता के बाद देश पर कांग्रेस का 50 वर्षों तक प्रत्यक्ष-परोक्ष शासन रहा। इस दौरान कांग्रेस तमिलनाडु (1967), बंगाल (1977), उत्तर प्रदेश (1989), गुजरात (1990), महाराष्ट्र (1995), ओडिशा (2000), गोवा (2012) और दिल्ली (2013) में ही एक बार सत्ता से बाहर हुई, मगर अपने दम पर अब तक सत्ता में नहीं लौट सकी। दिल्ली में 2015, 2020 और 2025 के चुनावों में वह खाता तक नहीं खोल पाई।

पिछले चार लोकसभा चुनाव स्पष्ट रूप से भारत के बदलते राजनीतिक परिदृश्य को रेखांकित करते हैं। 2009 में भाजपा को 18.8 प्रतिशत मत और 116 सीटें मिली थीं। 2014 में भाजपा 31 प्रतिशत मतों के साथ 282 सीटों पर पहुंच गई, तो कांग्रेस 206 से घटकर 44 सीटों और 28.5 प्रतिशत मतों से गिरकर 19.3 प्रतिशत पर आ गई। दोनों चुनावों में केंद्र में कांग्रेसनीत संप्रग सरकार सत्ता में थी। भाजपा के प्रति जनसमर्थन 2019 में और प्रबल हुआ और उसने पहले से अधिक मतों (37.3 प्रतिशत) और सीटों (303) के साथ फिर बहुमत प्राप्त किया। 2024 का चुनाव भी भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में सत्ता-विरोधी लहर, विपक्षी एकजुटता, भारत-विरोधी शक्तियों के प्रपंचों और नकारात्मक प्रचार के बीच लड़ा, जिसमें उसकी सीटें (240) और मत (36.5 प्रतिशत) दोनों घटे, पर सरकार बनाने में सफल रही।

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि केंद्र में मोदी सरकार रहते हुए पिछले 11 वर्षों में कई राज्यों में विपक्षी दलों ने भी चुनाव जीते। बंगाल में तृणमूल, तमिलनाडु में द्रमुक, झारखंड में झामुमो, कर्नाटक-हिमाचल-तेलंगाना में कांग्रेस, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और केरल में वामपंथी आदि शामिल हैं। यहां तक कि 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आप ने 2015 में 67 और 2020 में 62 सीटें जीतीं, तो 2022 में पंजाब की भी 80 प्रतिशत सीटें भी आप जीतने में सफल रही थी। यदि चुनाव आयोग किसी एक के लिए पक्षपाती होता, तो क्या ऐसे एकतरफा परिणाम संभव होते? वास्तव में कांग्रेस नेतृत्व सहित अधिकांश विरोधी दल अपनी मूल समस्या को देखने-समझने की क्षमता खो चुके हैं। अहंकार और वंशवादी अधिकारबोध ने इन्हें आत्मविश्लेषण से वंचित कर दिया है। वे कल्पना में जीते हुए वास्तविकता से पूरी तरह कट गए हैं और अपनी हर चुनावी असफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग पर अनर्गल आरोप मढ़ रहे हैं। एक कटु सत्य यह भी है कि यदि किसी कारण मतदाताओं का भाजपा से मोहभंग होता भी है तो मतदाता कांग्रेस के बजाय अन्य विकल्प खोजते हैं। देखा जाए तो सपा, राजद, तृणमूल, द्रमुक, राकांपा, आप ने कांग्रेस की ही सियासी जमीन हथियार कर ही अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत की हैं। सच यह है कि जब 'लोक' अर्थात मतदाता बार-बार विपक्ष को नकार देता है, तब संगठित राजनीतिक रणनीति के तहत एक 'तंत्र' चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करता है। उद्देश्य केवल इतना है कि जनता से कटाव के बीच अपनी गिरती राजनीतिक प्रासंगिकता किसी तरह बची रहे, भले ही इसके लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को ही आघात क्यों न पहुंचे।

## अभियान

# रामगंज बालाजी की अनसुनी कथा: जहाँ हनुमान स्वयं भक्तों की

राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र अपनी वीरता, इतिहास और आध्यात्मिक वैभव के लिए प्रसिद्ध है। इसी भूमि पर बूंदी जिले के निकट स्थित है रामगंज का वह अलौकिक धाम, जहाँ एक ऐसा बालाजी विराजमान हैं जिनकी कृपा पाने के लिए भक्तों को न मंत्र चाहिए, न विशेष पूजन, न कोई भेंट—बस सच्चा मन और पवित्र भावना। कहते हैं कि यहाँ पहुंचते ही हनुमान जी स्वयं भक्तों की मनोकामना समझ लेते हैं, जैसे किसी पिता को अपने बच्चे की इच्छा का अहसास हो। इस मंदिर में विराजे हनुमान जी को बालाजी, बजरंगबली, संकटमोचक और हनु जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, पर उनकी शक्ति किसी एक नाम में सीमित नहीं—वह तो उस परम भक्ति की धारा हैं, जो रामभक्ति की अनंत ज्योति के साथ बहती है। महाभारत, रामायण और पुराणों में हनुमान जी की लीला ही ऐसी रही है कि उनका कोई भी वर्णन छोटा नहीं हो सकता। उनका वह अद्भुत प्रसंग तो सबने सुना है जब बाल अवस्था

में सूर्यदेव को फल समझकर निगल लिया था। वही तेज, वही दिव्यता, वही तेजोमय आभा रामगंज के बालाजी में आज भी प्रतिबिंबित होती है।

बूंदी से लगभग आठ किलोमीटर दूर यह बालाजी धाम विरक्त भूमि की तरह प्रतीत होता है—जहाँ पहुँचते ही मन में एक अनोखी शांति उतरती चली जाती है। मंदिर उम्र में भले ही कुछ दशकों पुराना बताया गया हो, पर इसकी स्थापत्य शैली साफ दर्शाती है कि इसका निर्माण हाड़ा राजपूतों के समय का है। इसका प्रवेश द्वार बूंदी किले के झूला चौका के बिल्कुल समान प्रतीत होता है, मानो इतिहास स्वयं यहाँ आकर ठहर गया हो। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सामने एक अनुपम दृश्य दिखाई देता है—हनुमान जी की स्वर्ण आभा से चमकती दिव्य मूर्ति, और उनके ठीक सामने प्रतिष्ठित है राम दरबार। ऐसा लगता है कि भक्त पहले बालाजी के चरणों में पहुंचता है और फिर सीधे राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन प्राप्त कर लेता है। इस क्रम में एक आध्यात्मिक अनुभूति है, मानो हनुमान जी स्वयं भक्त को पकड़कर प्रभु के चरणों तक ले जाते हों।

हनुमान जी की मूर्ति यहाँ अनूठी है। वह बैठे हुए प्रतीत होते हैं, चेहरा स्वर्णिम दमकता है और मुखमंडल पर अद्भुत तेज झलकता है। पर सबसे विशिष्ट और अद्भुत है उनके हाथ में कमल का फूल। यह सामान्य बात नहीं। अन्य बालाजी मंदिरों में गदा, ध्वजा या परशु देखा जाता है, पर रामगंज में बालाजी कमल का फूल धारण किए हुए हैं। कमल का यह पुष्प केवल अलंकरण नहीं, बल्कि एक दिव्य संकेत है।

कमल का महत्व सनातन दर्शन में बहुत गहरा है—शुद्धता, ज्ञान, वैराग्य और आत्मशक्ति का प्रतीक। और हनुमान जी के हाथ में कमल तो और भी गूढ़ रहस्य प्रकट करता है। लोककथाओं में एक उल्लेख मिलता है कि भगवान राम के पूजन के समय 108 नील कमल लाने की जिम्मेदारी हनुमान जी को थी। जब एक कमल कम पड़ गया, तो बिना कोई विलंब किए हनुमान जी ने अपना एक नेत्र ही प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। इस कथा का सार यह है कि प्रेम और भक्ति में संख्या का कोई अर्थ नहीं—जहाँ समर्पण हो, वहाँ पूर्णता स्वयं उपस्थित हो जाती है।

यही समर्पण, यही प्रेम इस मंदिर की प्रतिमा में झलकता है। भक्तों का अनुभव है कि यहाँ मन में जो चाह लेकर आए, वह स्वयं बालाजी तक पहुँच जाती है। यहाँ न किसी विशेष आरती का बंधन है, न कोई जटिल विधि। केवल सच्ची श्रद्धा चाहिए। अनेक भक्तों ने यह अनुभव किया कि उनके बिना कहे ही उनकी मनोकामना पूर्ण हुई—किसी की बीमारी ठीक हो गई, किसी का खोया आत्मविश्वास लौट आया, किसी के बिगड़े संबंध सुधर गए, किसी का रुका हुआ कार्य पूर्ण हो गया। जैसे बालाजी मन पढ़ लेते हों।

इस मंदिर की भूमि में एक विशेष ऊर्जा है—यहाँ खड़े होते ही भीतर एक सकारात्मक कंपन उठता है, जैसे हृदय पर जमी धूल अचानक उड़ गई हो। यहाँ से लौटने वाला हर भक्त कहता है कि वह मन में हल्का, शांति से भरा और भीतर से मजबूत होकर लौटता है। यात्रा की दृष्टि से यह स्थान अत्यंत सरल है। कोटा से बस, ट्रेन और हवाई मार्ग से आने वाले यात्री बूंदी पहुंचकर यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। मंदिर द्वारा यात्रियों के ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था भी की जाती है, ताकि किसी भक्त को कोई असुविधा न हो। यह धाम समय के साथ और भी सुगम और व्यवस्थित होता जा रहा है।

पर इस स्थान का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी वास्तुशिल्प या सुव्यवस्था नहीं—बल्कि वह अदृश्य शक्ति है जो बालाजी की प्रतिमा से निकलती है। यहाँ हनुमान न केवल भक्तों के संकट हरते हैं, बल्कि उनकी आत्मा को मजबूत बनाते हैं।

रामगंज बालाजी केवल एक मंदिर नहीं—

यह वह स्थान है जहाँ हनुमान स्वयं अपने भक्तों के मन की पीड़ा पढ़ते हैं,

और राम की कृपा उनके जीवन में अवतरित कर देते हैं।

यह धाम श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति का स्रोत है, और भक्तों के लिए प्रभु से सीधा संवाद है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

# संयुक्त राष्ट्र के FAO और भारत की साझेदारी से देश में नेक्स्ट जेन 'स्मार्ट ब्लू रिवॉल्यूशन', गुजरात के जखाऊ में भी बनेगा विश्वस्तरीय ब्लू हार्बर मॉडल

- जखाऊ (गुजरात), वनकबारा (दमन-दीव) और कराईकल (पुडुचेरी) में विकसित होंगे विश्वस्तरीय ब्लू हार्बर मॉडल
- PMMSY के तहत 452.32 करोड़ रुपये की स्मार्ट फिशिंग अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू
- आगामी VGRC में कच्छ-सौराष्ट्र के तटीय विकास और ब्लू इकॉनमी पर रहेगा विशेष फोकस

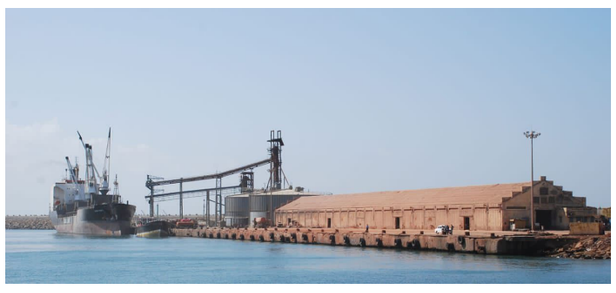

**(जीएनएस)**। गांधीनगर : गुजरात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारत की ब्लू इकोनॉमी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में उसका नेतृत्व सिर्फ दूरदर्शी ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक और परिणाम-केंद्रित भी है। तेजी से बदलते समुद्री परिदृश्य में आज फिशिंग हार्बर सिर्फ संरचनात्मक सुविधाएँ नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, समुद्री आजीविका और तटीय समुदायों की समृद्धि के प्रमुख स्तंभ बन चुके हैं। इसी दृष्टिकोण के केंद्र में है गुजरात द्वारा विकसित की जा रही "ब्लू हार्बर" अवधारणा, जो पर्यावरणीय स्थिरता, आर्थिक दक्षता और सामाजिक समावेशन को एक साथ लेकर चलती है।

राष्ट्रीय स्तर पर भी तटीय अवसंरचना को नई गति देने के प्रयास तेज हो गए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में मत्स्य विभाग (DoF), मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के साथ एक ऐतिहासिक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी के तहत जखाऊ (गुजरात), वनकबारा (दमन-दीव) और कराईकल (पुडुचेरी) में विश्व-स्तरीय "ब्लू हार्बर" स्थापित किए जाएंगे जो देश में स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी मत्स्य अवसंरचना के नए राष्ट्रीय मानक गढ़ेंगे।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत 452.32 करोड़ रुपये के निवेश से स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएँ तटीय विकास को तेज़ी से बदल रही हैं। इन परियोजनाओं से न सिर्फ समुद्री मत्स्य व्यवसाय आधुनिक होगा बल्कि भारत के वैश्विक समुद्री-आहार बाजार में भी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढ़ेगा।

कच्छ जिले के पश्चिमी छोर पर स्थित जखाऊ हार्बर गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मत्स्य केंद्रों में से एक है और यह राज्य की ब्लू ग्रोथ विज़न का प्रमुख आधार भी बना हुआ है। मत्स्य आयुक्त (COF) द्वारा प्रबंधित यह हार्बर हजारों मत्स्य-जीवियों के जीवन का केंद्र है और समुद्री सुरक्षा दृष्टि से भी अत्यंत रणनीतिक है। जेटी, मरम्मत क्षेत्र, भंडारण प्रणालियों और कटाई-परवर्ती सुविधाओं से लैस जखाऊ को हाल ही में "ब्लू रिवॉल्यूशन" पहल में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य इसकी अवसंरचनात्मक क्षमता को आधुनिक वैश्विक मानकों तक ले जाना है।

इसी पृष्ठभूमि में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह में राजकोट में आयोजित होने जा रही है। कच्छ और सौराष्ट्र जो अपने समृद्ध मत्स्य संसाधनों, महत्वपूर्ण समुद्री हार्बर्स और मजबूत तटीय अवसंरचना के लिए देशभर में प्रसिद्ध है, पर इस बार विशेष फोकस रहेगा । यह क्षेत्र न सिर्फ समुद्री मत्स्य क्षेत्र के गतिविधियों और वैल्यू-चेन लॉजिस्टिक्स के प्रमुख द्वार हैं बल्कि भारत की उभरती ब्लू इकोनॉमी के लिए भी महत्वपूर्ण इंजन बन रहे हैं। सम्मेलन में नीति-निर्माताओं से लेकर उद्योग जगत के नेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और प्रमुख हितधारकों तक सभी एक मंच पर आएंगे जिसका उद्देश्य नए निवेश अवसरों, नवाचारों, उभरती तकनीकों और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक साझा दृष्टि विकसित करना।

# अहमदाबाद मण्डल पर बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मण्डल में आज मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में भारतीय संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर के 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश, अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्रीमती मंजू मीणा तथा अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री विकास गढ़वाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने डॉ. बी.आर.अम्बेडकर की छवि पर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्ज्वलित कर उन्हें नमन किया।

कार्यक्रम में मण्डल के रेल अधिकारी, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि, ओबीसी एसोसिएशन, एससी/एसटी एसोसिएशन के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों ने उपस्थित होकर डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

# स्पेशल खेल महाकुंभ में 'वोरियर' टीम का शानदार प्रदर्शन, लगातार तीसरी बार गोल्ड मेडल पर कब्जा

**(जीएनएस)**। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं गुजरात सरकार की प्रेरणा से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले विशेष खेल महाकुंभ में दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा ने एक बार फिर अपनी उड़ान भरी है। इसी कड़ी में श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल (कप्तान) के नेतृत्व में 'वोरियर' टीम ने पेरा सिटिंग वॉलीबॉल खेल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।

यह प्रतियोगिता दिनांक 07/12/2025 (रविवार) को सिदसर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इनडोर स्टेडियम, भावनगर में पेरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन, भावनगर की अगुवाई में सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भावनगर जिले की कुल 7 टीमों ने भाग लिया, जिन सभी को पराजित करते हुए 'वोरियर' टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। गौरतलब है कि 'वोरियर' टीम ने यह खिताब लगातार तीसरी बार जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। यह उपलब्धि टीम की कड़ी मेहनत, अनुशासन और कप्तान श्री पराक्रमसिंह गोहिल के कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

दिव्यांग कर्मचारी श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल वर्तमान में पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में वाणिज्यिक विभाग में मुख्य वाणिज्य क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। अब जनवरी 2026 में श्री पराक्रमसिंह कनुभा गोहिल की अगुवाई में 'वोरियर' टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपने चैम्पियनशिप खिताब का बचाव (डिफेंड) करने हेतु नडियाद के लिए रवाना होगी। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी, मंडल वाणिज्य प्रबंधक सुश्री नीलादेवी झाला एवं भावनगर मंडल के सभी शाखा अधिकारियों ने उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और भविष्य में उनकी शानदार उपलब्धियों की कामना की।

# पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पर कड़ी निगरानी: पांच नए स्पेशल ऑब्जर्वर तैनात, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास

**(जीएनएस)**। कोलकाता। आगामी चुनावों की तैयारी के मद्देनजर केंद्रीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की निगरानी को और सख्त कर दिया है। राज्य में पहले से ही नियुक्त स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के बाद अब आयोग ने पांच डिवीजनों में नए स्पेशल रोल ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। यह कदम विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फॉर्म वितरण, संग्रह, डिजिटाइजेशन और ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने से पहले सभी गतिविधियों पर त्रुटिरहित निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गलती, अनियमितता या लापरवाही को रोकने के लिए ईसीआई ने निरीक्षण व्यवस्था को और कड़ा कर दिया है। इससे यह संदेश भी जाता है कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। आयोग के सूत्रों के अनुसार, नए ऑब्जर्वरों की नियुक्ति से मतदाता सूची से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और आगामी चुनावों में किसी भी विवाद की संभावना कम होगी।

पांच डिवीजनों में नियुक्त नए ऑब्जर्वरों की सूची इस प्रकार है: प्रेसिडेंसी डिविजन (कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, नदिया) में रविकांत, मेदिनीपुर डिविजन (पश्चिम/पूर्व मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया) में नीरज कुमार बनसोर, बर्दवान डिविजन (बीरभूम, पश्चिम/पूर्व बर्दवान, हुगली) में कृष्ण कुमार निराला, मालदा डिविजन (मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर/दक्षिण दिनाजपुर) में आलोक तिवारी और जलपाईगुड़ी डिविजन (दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरदुआर) में पंकज यादव। इन ऑब्जर्वरों का कार्य मतदाता सूची से जुड़ी सभी गतिविधियों का निरंतर निरीक्षण करना और किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना होगा।

इससे पहले सेवानिवृत्त आईएएस सुब्रत गुप्ता को एसआईआर की संपूर्ण व्यवस्था की समीक्षा और राज्य में विशेष निरीक्षण का कार्यभार सौंपा गया था। अब डिवीजन स्तर पर नई तैनाती से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आयोग मतदाता सूची की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा।

राज्य के चुनाव अधिकारी भी पूरी तरह सक्रिय हैं और उन्होंने बताया कि सभी आवश्यक उपाय समयबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। मतदाता सूची में सुधार और अद्यतन को सुनिश्चित करने के लिए डाटा संग्रह, फॉर्म वितरण और डिजिटाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम मतदाता सूची की विश्वसनीयता बढ़ाने और चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी है।

विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की कड़ी निगरानी से मतदाता सूची में त्रुटियों की संभावना कम होगी और चुनावी प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास मजबूत होगा। नए ऑब्जर्वरों की जिम्मेदारी केवल निरीक्षण तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वे स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन भी देंगे, ताकि सभी प्रक्रियाएं नियमों और दिशानिर्देशों के अनुरूप पूरी हों।

इस अभियान से न केवल मतदाता सूची की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि राज्य में चुनावी तैयारियों की गति भी बढ़ेगी। आयोग की यह पहल यह संदेश देती है कि लोकतंत्र में हर नागरिक की भागीदारी और हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी और सख्ती दोनों बढ़ेगी और यह चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

# जूनियर एनटीआर की पहचान के अनधिकृत उपयोग पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को त्वरित कार्रवाई का निर्देश

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। तेलुगु सुपरस्टार नंदमुरी तारक रामाराव जूनियर, जिन्हें आमतौर पर जूनियर एनटीआर के नाम से जाना जाता है, की पहचान, नाम और तस्वीर का बिना अनुमति उपयोग करने वाले मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स साइट्स को तीन दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह निर्देश तब दिया, जब जूनियर एनटीआर की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जूनियर एनटीआर की शिकायत को आईटी एक्ट के तहत औपचारिक शिकायत की तरह दर्ज किया जाए और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसमें विस्तृत आदेश जारी होने की संभावना है।

हाईकोर्ट हाल के दिनों में सेलिब्रिटी और सार्वजनिक हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार सक्रिय है। इससे पहले 27 नवंबर को अभिनेता अजय देवगन की पहचान से जुड़े कंटेंट के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगाई गई थी। अदालत ने एआई और डीपफेक तकनीक से बनाए गए वीडियो और डिजिटल सामग्री को इंटरनेट से हटाने के निर्देश भी जारी किए थे।

इसके अलावा अदालत ने हाल के आदेशों में कई अन्य हस्तियों की पहचान के दुरुपयोग पर भी रोक लगाई है, जिनमें अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर, अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और निर्माता करण जौहर शामिल हैं। इन आदेशों का उद्देश्य डिजिटल युग में सेलिब्रिटी व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को मजबूत करना और उनके बिना अनुमति उपयोग को रोकना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अनधिकृत कंटेंट तेजी से फैलता है और सेलिब्रिटीज़ की पहचान, प्रतिष्ठा और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं, जो न केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाते हैं बल्कि आम उपयोगकर्ताओं को भी चेतावनी देते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी की पहचान का दुरुपयोग गंभीर कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकता है।

डिजिटल युग में व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा और सेलिब्रिटी की पहचान के सुरक्षित उपयोग की दिशा में यह कदम न्यायालय की सक्रियता और कानून की सख्ती का स्पष्ट संदेश देता है। अदालत ने प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वे जूनियर एनटीआर की पहचान से जुड़े सभी अनधिकृत कंटेंट को हटाने, प्रभावित सामग्री की पहचान करने और भविष्य में ऐसे उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रभावी प्रणाली लागू करें।

विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदेश केवल जूनियर एनटीआर तक सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे उद्योग और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए मिसाल कायम करता है। इस निर्णय से स्पष्ट संकेत जाता है कि सेलिब्रिटीज़ के व्यक्तित्व अधिकारों का सम्मान और डिजिटल कंटेंट के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करना अब कानूनी दायरे में सख्ती से पालन किया जाएगा।

# भावनगर रेलवे मंडल पर मनाया गया डॉ. भीमराव आंबेडकर जी का 70वाँ "महापरिनिर्वाण दिवस"

**(जीएनएस)**। पश्चिम रेलवे के भावनगर रेलवे मंडल पर भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का 70वाँ महापरिनिर्वाण दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बाबा साहेब का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, जिसे प्रतिवर्ष महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

दिनांक 06 दिसंबर 2025 (शनिवार) को मंडल कार्यालय में प्रशासनिक अवकाश होने के कारण यह कार्यक्रम 8 दिसंबर 2025 (सोमवार) को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री हिमाँशु शर्मा सहित मंडल के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा दो मिनट का मौन रखकर उनकी स्मृति को नमन किया।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सभाकक्ष में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को स्मरण किया।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के विभिन्न ट्रेड यूनियनों, एससी/एसटी एसोसिएशन एवं ओबीसी एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में बाबा साहेब के विचारों, सामाजिक न्याय, समानता एवं संविधान के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम के माध्यम से बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करने तथा समाज में समता, बंधुत्व एवं न्याय के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।

# गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: चार नेपाली नागरिकों के शव नेपाल भेजे जाएंगे

**(जीएनएस)**। काठमांडू। भारत के गोवा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में चार नेपाली नागरिकों की मौत हो गई है। नेपाल दूतावास नई दिल्ली, गोवा सरकार के समन्वय में मृतकों के शवों को नेपाल लाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।

नेपाल के राजदूत डॉ. शंकर शर्मा ने बताया कि भारत के विदेश मंत्रालय के माध्यम से गोवा सरकार ने मृतकों की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सभी शव नेपाल भेज दिए जाएंगे। मृतकों में से दो की पहचान पहले ही चूर्ण बहादुर पुन और विवेक कटवाल, दोनों झापा जिले के निवासी, के रूप में हो चुकी है। शेष दो शवों की पहचान की प्रक्रिया और उनके घर का पता लगाने का काम अभी जारी है।

गोवा के अरपोरा क्षेत्र में स्थित इस नाइट क्लब में शनिवार मध्यरात्रि को लगी आग में कुल 25 लोगों की मौत हुई थी। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए राहत उपाय किए गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये और घायलों को पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।

नेपाल दूतावास ने मृतकों के परिजनों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है और उनके शवों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए गोवा प्रशासन के साथ समन्वय कर रहा है। राजदूत डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

इस घटना ने नाइट क्लब सुरक्षा और आपात प्रबंधन के महत्व को फिर से उजागर किया है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे की जांच के बाद ही आग लगने के कारण और संभावित सुरक्षा चूक के पहलुओं का पता चल सकेगा। गोवा प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए कड़े नियम और निगरानी बढ़ाई जाएगी।

# देशभर में फैले साइबर ठगी गिरोह का बड़ा भंडाफोड़, सोशल मीडिया पर 'निवेश गुरु' बनकर 6.33 करोड़ की ठगी, तीन गिरफ्तार

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे देशव्यापी साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सोशल मीडिया पर खुद को 'निवेश गुरु' और सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर बताकर लोगों से करोड़ों रुपये ठग रहा था। पुलिस ने गिरोह के तीन मुख्य संचालकों को गिरफ्तार किया है और 6.33 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा किया है। गिरोह के खिलाफ अब तक 165 साइबर शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं, जिससे स्पष्ट है कि यह नेटवर्क काफी बड़े पैमाने पर सक्रिय था और देशभर में लोगों को निशाना बना रहा था।

पुलिस की जांच के मुताबिक यह गिरोह सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन, फर्जी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट, नकली सेबी प्रमाणपत्र और बनावटी ट्रेडिंग ऐप दिखाकर लोगों को निवेश के भारी लाभ का लालच देता था। शुरुआत में पीड़ितों को हल्का सा मुनाफा दिखाकर उनका विश्वास जीता जाता था और फिर उन्हें बड़ी रकम निवेश करने के लिए उकसाया जाता था। जैसे ही पैसा उनके नेटवर्क में चला जाता, पीड़ितों को ब्लॉक कर दिया जाता या फर्जी तकनीकी दिक्कतों का बहाना बनाया जाता।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ओडिशा निवासी प्रवेश चंद्र पांडा, प्रीतम रोशन पांडा और श्रीतम रोशन पांडा के रूप में हुई है। ये तीनों ओडिशा में फैले एक बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क को संचालित कर रहे थे, जिसके जरिए ठगी की भारी भरकम रकम को कई परतों में घुमाकर असली स्रोत और सरगनाओं तक पहुंचाया जाता था। इनके पास से 17 मोबाइल फोन, 21 सिम कार्ड, 124 एटीएम/डेबिट कार्ड, दर्जनों पासबुक, चेक बुक और अन्य वित्तीय दस्तावेज बरामद हुए हैं।

इस गिरोह का भंडाफोड़ एक पीड़ित की शिकायत पर हुआ, जिसमें उसे भारी मुनाफे का भरोसा दिलाकर 49.73 लाख रुपये ठगे गए थे। जांच में पता चला कि यह रकम कई बिजनेस खातों के जरिये ओडिशा के म्यूल अकाउंट्स में भेजी गई थी और फिर धीरे धीरे एटीएम से निकालकर गिरोह के सरगनाओं तक पहुंचाई गई। पुलिस ने जब वित्तीय जांच को गहराई से खंगाला, तो पता चला कि इन खातों को केवल रकम के लेनदेन को छिपाने के लिए बनाया गया था।

जांच में यह भी सामने आया कि प्रवेश चंद्र पांडा गंजम जिले में 'श्रीजी अपैरल्स' नामक म्यूल अकाउंट का मुख्य संचालक था। वही बैंक खातों, सिम कार्डों और डिजिटल लेनदेन चैनलों की व्यवस्था देखता था। उसके भतीजे प्रीतम और श्रीतम रोशन पांडा इस नेटवर्क को तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। उनके फोन और डिजिटल रिकॉर्ड में उन लेनदेन से जुड़े साक्ष्य मिले हैं, जिनसे करोड़ों रुपये की ठगी को अंजाम दिया गया था।

क्राइम ब्रांच के अनुसार यह गिरोह चार चरणों में काम करता था। पहले चरण में सोशल मीडिया पर निवेश सलाहकार बनकर लोगों को फंसाया जाता था। दूसरे चरण में शुरुआती रकम बिजनेस खातों में डालकर पीड़ितों का भरोसा जीता जाता। तीसरे चरण में रकम को अलग अलग म्यूल अकाउंट्स में घुमाया जाता और चौथे चरण में नकदी निकालने वाली टीम एटीएम से पैसा निकालकर सरगनाओं को सौंप देती। यह बहु स्तरीय व्यवस्था इतनी जटिल थी कि आम व्यक्ति के लिए ठगी का पता लगाना almost असंभव हो जाता।

देशभर में तेजी से बढ़ रही साइबर ठगी को देखते हुए पुलिस इस केस को एक बड़ा ऑपरेशन मान रही है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरह के गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की वित्तीय जानकारी, उनकी रुचि और मनोविज्ञान का अध्ययन कर उन्हें निशाना बनाते हैं। पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों और मुख्य सरगनाओं की तलाश में जुटी है, जिनके विदेश में होने की भी आशंका है।

क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि किसी भी 'स्टॉक गुरु', 'इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट', 'प्री IPO ऑफर' या 'अत्यधिक मुनाफा' देने वाले ऑनलाइन दावों से सावधान रहें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी निवेश से पहले प्रमाणित स्रोतों और आधिकारिक वेबसाइटों की ही जांच करें।

# बाड़मेर में सड़क निर्माण का घोटाला - 15 साल बाद मिली सड़क दो दिन में उखड़ी, रेत पर बिछा दिया गया डामर; इलाके में गुस्से की लहर

**(जीएनएस)**। राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में झणकली से जुड़िया गांव को जोड़ने वाली वह सड़क, जिसका ग्रामीण 15 साल से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार बनी तो सही—but उम्मीदों का यह पुल दो दिन भी नहीं टिक पाया। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब सड़क पर डामर बिछा, गांव में उमंग दिखाई दी थी, लोगों को लगा था कि अब कीचड़, धूल और जर्जर रास्तों की परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन यह खुशी अधिक देर कायम नहीं रह सकी।

निर्माण पूरा होने के अगले ही दिन सड़क की ऊपरी परत उखड़ने लगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें सड़क की सतह हाथों से ही आसानी से उठती नजर आ रही है। सड़क जरा-सी दबाव में दरक जाती है, जैसे किसी ने पतले गोंद से कागज चिपका दिया हो। यह दृश्य देखकर ग्रामीण हैरान रह गए कि आखिर सड़क बनाई कैसे गई थी।

इलाके में रहने वाले लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार ने बिना कोई बेस लेयर तैयार किए सीधे रेत पर डामर बिछा दिया। सड़क निर्माण में सबसे अहम होता है उसकी मजबूत नींव—ग्रेवल, मोरम और बेस को अच्छी तरह दबाकर मशीनों से कम्पैक्ट किया जाता है। लेकिन इस सड़क पर ऐसा कुछ नहीं किया गया। जैसे-जैसे सड़कों का निरीक्षण करते ग्रामीण चलते गए, जगह—जगह डामर अपनी जगह से उठते गए। हालत यह थी कि सड़क को

हाथ से कुरेदकर भी नुकसान पहुंचाया जा सकता था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे काम के दौरान पीडब्ल्यूडी का एक भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। न जांच, न ट्रेनिंग, न क्वालिटी चेक—ठेकेदार को जैसे सारी छूट मिल गई हो। ग्रामीण कहते हैं कि जिस सड़क के लिए 15 सालों तक आवाज उठाई गई, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, अधिकारियों से बार-बार शिकायत की गई, वही सड़क अब गांव वालों के सामने मजाक बनकर खड़ी है।

सड़क पर चल रहे वाहन भी निर्माण की पोल खोलते दिखे। जैसे ही किसी बाइक या ट्रैक्टर ने सड़क पर पहिया रखा, सतह में दरारें पड़ने लगतीं। गर्मी, बारिश, ठंड—ऐसे मौसम जिनमें सड़कें अपनी गुणवत्ता साबित करती हैं—उसकी नौबत तक नहीं आई। सड़क तो दूसरे ही दिन जवाब दे गई।

इस मामले में शिव विधानसभा के विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क उनके क्षेत्र का बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, लेकिन सालों से खराब हालत में पड़ी थी। नई सड़क बनने की उम्मीद ही अब उनके लिए मायूसी का कारण बन गई है। लोगों में गुस्सा उबल रहा है—और जगह-जगह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी धन की इस खुली बर्बादी की जिम्मेदारी कौन लेगा?

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग से तत्काल जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ठेकेदार से जवाब लिया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सड़क को गुणवत्ता मानकों के अनुसार दोबारा बनाया जाए। उनका तर्क है कि यदि सही सामग्री, सही कम्पैक्शन और तकनीकी मानकों का पालन किया जाता, तो सड़क इतने कम समय में नहीं टूटती।

15 साल की उम्मीद, दो दिन में ढही—यह घटना न सिर्फ सिस्टम की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि सवाल उठाती है कि क्या ग्रामीणों के अधिकार और संसाधनों के प्रति सरकार और विभाग वास्तव में संवेदनशील हैं? क्या जांच होगी या फिर इस सड़क की तरह मामला भी कुछ समय बाद उखड़कर खत्म कर दिया जाएगा?

## नोएडा अदालत का बड़ा फैसला: सुंदर भाटी को 9 साल की सजा, फिर भी जेल से बाहर रहने का कानूनन आधार क्या?

**(जीएनएस)**। नोएडा की जिला अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी और उसके 10 साथियों के खिलाफ चल रहे बहुचर्चित गैंगस्टर एक्ट के मामले में सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने सभी 10 आरोपियों को 9-9 साल की कठोर कैद और 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। फैसला सख्त था, तर्क मजबूत थे, और अदालत ने अपराध के सिलसिले, संगठित नेटवर्क और अपराधियों के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए कठोर दंड का प्रावधान भी लागू किया।

लेकिन इसके बावजूद पूरा मामला उस वक्त चर्चा में आ गया जब अदालत के आदेश के बाद भी अधिकांश दोषियों को जेल नहीं भेजा गया। सवाल उठा—जब सजा 9 साल की सुनाई गई है, तो फिर ये गैंगस्टर तुरंत जेल क्यों नहीं जा रहे?

इस प्रश्न का उत्तर अदालत के आदेश, केस के पुराने रिकॉर्ड और आरोपियों के पहले से जेल में बिताए गए समय में छिपा है, जिसे अदालत ने "सजा की अवधि से अधिक कारावास" के रूप में माना।

अदालत ने पाया कि 10 में से 8 आरोपी ट्रायल के दौरान ही इतनी लंबी अवधि जेल में गुजार चुके थे, जो अब सुनाई गई सजा से भी अधिक थी। कानून कहता है कि यदि कोई आरोपी सुनाई गई सजा से अधिक समय पहले ही जेल में काट चुका है, तो ऐसी स्थिति में उसे दोबारा सजा काटने के लिए जेल नहीं भेजा जाता। इसलिए 8 दोषियों को फैसला सुनते ही रिहा कर दिया गया।

हालांकि सिंहराज भाटी और ऋषिपाल पर यह नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी कुल घोषित सजा से कम अवधि जेल में बिताई थी। इसलिए दोनों को फिर से जेल भेज दिया गया।

8 फरवरी 2015 को दादूपुर के ग्राम प्रधान और सपा नेता हरेंद्र नागर अपने सरकारी गनर भूदेव शर्मा के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। निथाना गांव के पास एक योजनाबद्ध घात लगाकर हमला हुआ। हरेंद्र नागर और उनका गनर मौके पर ही मारे गए। भिड़ंत के दौरान बदमाश जतिन खत्री भी ढेर हो गया।

हरेंद्र नागर और सुंदर भाटी के बीच सरिया चोरी, फैक्ट्री स्क्रैप, पानी सप्लाई और ठेकेदारी को लेकर लंबे समय से चल रही आर्थिक रंजिश बड़ी वजह थी। इसी दुश्मनी के चलते हत्या की सुपारी दी गई और उसकी साजिश रची गई।

अप्रैल 2021 में इसी हत्याकांड में अदालत सुंदर भाटी सहित 12 को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है, जिसकी अपील अभी हाई कोर्ट में लंबित है।

तीन दशक से ज्यादा समय से दिल्ली–एनसीआर और पश्चिमी यूपी में सुंदर भाटी का नाम अपराध, दहशत और दबदबे का पर्याय बना हुआ है। उसके गैंग में रंगदारी, सुपारी किलिंग, जमीन कब्जा, फैक्ट्री स्क्रैप सिंडिकेट, सरिया चोरी, कारोबारी दबाव और खनन से जुड़े कई अपराधों का लंबा इतिहास रहा है। वर्ष 2023 में एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना को भी भाटी गैंग का हिस्सा माना जाता था।

अतीक और अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में हत्या के समय सुंदर भाटी का नाम चर्चा में आया था, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई।

## गुजरात की लेडी डॉक्टर की सुपारी किलिंग का खुलासा - राजस्थान के बदमाशों ने 15 लाख में किया था सौदा, एक लाख एडवांस भी ले लिए; पुलिस ने वारदात होने से पहले रोकी हत्या

**(जीएनएस)**। राजस्थान के झुंझुनूं जिले में पुलिस ने एक ऐसी सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश किया है, जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। यह मामला न सिर्फ अपराधियों की खौफनाक सोच को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि समय रहते पुलिस की कार्रवाई किसी मासूम की जान बचा सकती है। झुंझुनूं पुलिस ने गुजरात की एक महिला डॉक्टर की हत्या की सुपारी का खुलासा करते हुए छह अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से विदेशी पिस्टल, सात जिंदा व चार खाली कारतूस बरामद किए गए।

राजस्थान के पिलानी थाना क्षेत्र का लिखवा गांव इस कहानी का मूल केंद्र है। कुछ दिन पहले गांव में शराब के ठेकेदार को रंगदारी के लिए धमकाया गया था। अपराधियों ने ठेकेदार को डराने के लिए फायरिंग भी की। पुलिस ने जब इस फायरिंग की जांच शुरू की तो उन्हें बिल्कुल अलग दिशा में ले गई—a

direction जो एक हत्या की गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही थी।

मुख्य आरोपी हिमांशु जाट को गिरफ्तार किया गया तो पूछताछ में उसने ऐसा सच उगला कि पुलिस भी चकित रह गई। हिमांशु ने बताया कि ठेकेदार पर फायरिंग की घटना के ठीक बाद वह और उसके साथी गुजरात जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका मकसद गुजरात में रहने वाली एक लेडी डॉक्टर की हत्या करना था। हत्या की सुपारी उन्हें 15 लाख रुपये में मिली थी। अपराधियों को अग्रिम तौर पर एक लाख रुपये एडवांस भी दे दिए गए थे।

यह सुपारी गुजरात के बडोदरा में काम करने वाले अनुज शर्मा द्वारा दिलवाई गई थी। अनुज ने यह पूरा समझौता लिखवा गांव के भूपेंद्र मेघवाल और सचिन उर्फ कालू मेघवाल के जरिए तय करवाया। तय प्लान के अनुसार एक लाख रुपये अग्रिम दिए गए। इसी रकम से आरोपी मनोज मेघवाल और आकाश उर्फ बिट्टू मेघवाल जयपुर पहुंचे और वहां उत्तर प्रदेश के अवैध हथियार सप्लायर से विदेशी पिस्टल और 11 कारतूस खरीद लिए।

हथियार मिलने के बाद प्लान ने तेजी पकड़ी। हिमांशु, आकाश, मनोज और सचिन एक कार में गुजरात के लिए निकल पड़े। वहां अनुज शर्मा ने उन्हें उस महिला डॉक्टर की तस्वीर दिखाई और उसका पूरा घर, क्लिनिक और आने-जाने के रास्तों की रैकी करवाई। यानी हत्या की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी—हथियार तैयार, फोटो तैयार, लोकेशन तय और सुपारी के पैसे भी हाथ में।

लेकिन किस्मत ने डॉक्टर का साथ दिया। रंगदारी और फायरिंग के मामले में पुलिस की तेज कार्रवाई के चलते आरोपी समय पर पकड़े गए। फायरिंग केस में हुई गिरफ्तारी ने पूरे मर्डर प्लान को रोक दिया। अगर पुलिस कुछ दिनों की देरी कर देती, तो गुजरात में एक निर्दोष महिला डॉक्टर की हत्या हो चुकी होती। झुंझुनूं पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के अनुसार, यह गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है। इससे न सिर्फ एक खतरनाक अपराध होने से रुका है, बल्कि एक अपराधी गिरोह की गहरी साजिश भी सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस साजिश में और कौन शामिल था, हत्या की वजह क्या थी और अनुज शर्मा ने डॉक्टर को क्यों निशाना बनाया। फिलहाल सभी आरोपियों पर केस दर्ज कर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस की इस समय पर हुई कार्रवाई ने न सिर्फ एक गैंग को रोक दिया बल्कि एक जान बचा ली—और शायद कई और अपराधों को भी रोक दिया जो भविष्य में यह गैंग अंजाम दे सकता था। झुंझुनूं के लोग इस मामले को एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने साबित कर दिया कि जब सिस्टम सतर्क हो, तो अपराधी कितना भी बड़ा प्लान बना लें—उनके कदमों को रोका जा सकता है।

## जबलपुर में चाउमीन के ठेले पर खड़ी रंजिश ने ली जान — सॉस को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, चाकू से ताबड़तोड़ वार कर मोनू की हत्या

**(जीएनएस)**। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की शांत दिखने वाली शक्तिनगर चौपाटी रविवार देर रात अचानक चीख-पुकार, खून और भगदड़ से भर उठी। एक मामूली सी बात, चाउमीन में "थोड़ा और सॉस" डालने को लेकर हुई बहस, धीरे-धीरे ऐसी रंजिश में बदल गई कि 45 वर्षीय मोनू चक्रवर्ती की जान ले ली गई। शक्तिनगर की वही चौपाटी, जहां रोजाना परिवार, युवा और बच्चे शाम बिताने आते हैं, उसी जगह चाकुओं की चमक और वारों की आवाज़ में दहशत फैल गई।

मोनू चक्रवर्ती वर्षों से यहां चाउमीन का ठेला लगाते थे। उनके ठेले के सामने खिलखिलाहट, दोस्तों की गपशप और परिवारों का शोर सुना जाता था। रविवार को भी मोनू पहले की ही तरह अपने ग्राहकों को गर्म चाउमीन परोस रहे थे, तभी अचानक वह घटना unfolded हुई जिसने पूरा इलाका हिलाकर रख दिया।

तीन दिन पहले अमन चक्रवर्ती नाम के एक स्थानीय बदमाश ने मोनू के ठेले पर आकर उनसे चाउमीन में "और सॉस डालने" को कहा था। उस दिन हल्की-फुल्की कहा-सुनी हुई, लेकिन मोनू ने बात को वही खत्म कर दिया था। लेकिन अमन के अंदर गुस्सा पनप चुका था—एक

ठेला लगाने वाले ने उसकी बात क्यों नहीं मानी?

इसी रंजिश को दिल में दबाए अमन रविवार रात अपने दो साथियों ताशु यादव और रोहित झारिया के साथ मोनू के ठेले पर आ धमका। इलाके के लोगों के मुताबिक, आते ही तीनों ने मोनू को गालियां देनी शुरू कर दीं। जब मोनू ने शांत होकर उन्हें समझाने की कोशिश की, तो अमन और उसके साथियों ने अचानक हमला बोल दिया।

तीनों मोनू पर टूट पड़े। मारपीट शुरू हुई और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अमन ने चाकू बाहर निकालकर मोनू को जमीन पर गिरा दिया। देखते ही देखते ताबड़तोड़ वार शुरू हो गए। चाऊमीन की खुशबू और खाने का शोर गायब हो चुका था—अब बस चीखें थीं और चारों तरफ अफरा-तफरी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी तब तक चाकू मारते रहे, जब तक मोनू का शरीर निढाल नहीं हो गया। लोग डर से दूर हटते रहे, कोई बीच में नहीं आया—आरोपी अत्यंत उग्र और अनियंत्रित दिखाई दे रहे थे। चाकुओं के वारों की चमक और खून से सनी जमीन ने पूरे चौपाटी को कुछ ही मिनटों में वारदात का भयानक मैदान बना दिया। हमला करने के बाद तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोग हिम्मत जुटाकर मोनू को अस्पताल ले गए, लेकिन उनकी सांसें अस्पताल पहुंचने से पहले ही थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मोनू की मौत की खबर फैलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन शव को लेकर सीधे चौपाटी पहुंचे और सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया। मातम, गुस्सा और इंसाफ की मांग से पूरा इलाका गूंज उठा। महिलाओं ने चौक को घेर लिया, सड़क बंद कर दी गई और देर रात तक विरोध के स्वर हवाओं में तैरते रहे।

गढ़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, भीड़ को समझाया, लेकिन आक्रोश इतना तीखा था कि शांत होने में देर लगी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू की।

CSP आशीष जैन ने बताया कि तीन आरोपियों में से एक रोहित झारिया को हिरासत में ले लिया गया है। जबकि मुख्य आरोपी अमन चक्रवर्ती और उसका साथी ताशु यादव अब भी फरार हैं। पुलिस की तीन टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

एक और दिलचस्प पहलू यह है कि आरोपियों की ओर से दावा किया जा रहा था कि हमले के दौरान रोहित खुद चाकू से घायल हुआ, लेकिन मौके के वीडियो फुटेज और गवाहों में इसका स्पष्ट सबूत नहीं है। पुलिस इस दावे की अलग से जांच कर रही है। साथ ही, जिस नंदू तिवारी नाम के व्यक्ति का परिजनों ने नाम लिया है, उसकी भूमिका भी छानबीन में जोड़ी गई है।

पुलिस यह भी देख रही है कि आरोपी पहले से किन आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इलाके के लोगों के अनुसार, अमन और उसके दो साथी स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाने के लिए बदनाम हैं।

मोनू की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के उस भयावह सच का आईना है जिसमें छोटी-छोटी बातों पर लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। मोनू चक्रवर्ती अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में सिर्फ चाउमीन परोसते थे—किसी का बुरा नहीं किया, किसी से दुश्मनी नहीं रखी। लेकिन एक प्लेट चाउमीन में "थोड़ा और सॉस" न डालना उनकी मौत की वजह बन गया।

शहर आज इस सवाल से जूझ रहा है कि आखिर किस ओर बढ़ रहा है हमारा समाज? क्या एक ठेला लगाने वाले की जान इतनी सस्ती है? क्या बदमाशों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि सरेआम हत्या कर फरार हो जाएं?

## सुप्रीम कोर्ट में उठे संवैधानिक सवालों के बीच राजस्थान के धर्मांतरण विरोधी कानून पर बढ़ी कानूनी सरगर्मी

**(जीएनएस)**। नई दिल्ली की सर्द सुबह में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही एक ऐसे मामले के साथ आगे बढ़ी जिसने देश भर में एक बार फिर धर्मांतरण, धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य की शक्ति के बीच संतुलन पर तीखी बहस छेड़ दी है। अदालत ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए 2025 में लागू राजस्थान अनधिकृत धर्मांतरण निषेध अधिनियम की संवैधानिक वैधता पर विस्तृत जवाब मांगा है। यह नोटिस कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की उस याचिका पर जारी हुआ है जिसमें इस कानून को 'अल्ट्रा वायर्स', यानी संविधान की मूल भावना के विपरीत बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई है।

याचिका की सुनवाई दो-न्यायाधीशों की पीठ, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, के समक्ष हुई। पीठ ने स्पष्ट किया कि कानून में शामिल कई कठोर प्रावधान गंभीर संवैधानिक प्रश्न खड़े करते हैं, इसलिए राज्य सरकार को इसे न्यायिक कसौटी पर खरा साबित करने के लिए उचित तर्क रखने होंगे। पीठ ने इस याचिका को उन सभी लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया है जिनमें देश के अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को भी चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को अवगत कराया कि समान मुद्दों वाली कई याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं और यह मामला किसी एक राज्य तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की व्यापक बहस से जुड़ा है। मेहता ने यह भी कहा कि अदालत को सभी राज्यों के पक्ष आने के बाद समग्र रूप से निर्णय लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कानूनी भ्रम या विरोधाभास न रहे।

राजस्थान के 2025 के अधिनियम को देश के सबसे कठोर धर्मांतरण-रोधी कानूनों में माना जा रहा है। इस कानून में सामूहिक और धोखे से किए जाने वाले धर्मांतरण पर 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। साधारण धोखाधड़ी या छल से किए गए धर्मांतरण पर 7 से 14 साल की सजा दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि अपराध किसी नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति–जनजाति समुदाय या दिव्यांग व्यक्ति के साथ किया गया हो तो 10 से 20 साल तक की कठोर सजा और न्यूनतम 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि यह कानून कमजोर वर्गों को संरक्षण देने हेतु आवश्यक है, जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इससे नागरिकों के व्यक्तिगत और धार्मिक अधिकारों पर अनावश्यक अंकुश लगता है।

उधर, इसी मुद्दे पर सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों के कानूनों पर भी सुनवाई की थी। तब अदालत ने साफ किया था कि सभी राज्यों से जवाब मिलने के बाद ही कानूनों पर रोक लगाने की किसी मांग पर विचार किया जाएगा। अदालत का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वह इस संवेदनशील विषय पर जल्दबाज़ी में कोई निर्णय नहीं देना चाहती, बल्कि व्यापक कानूनी और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए एक संगत निर्णय की ओर बढ़ रही है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से राजस्थान सरकार को दिया गया यह नोटिस इस बहस को एक निर्णायक मोड़ पर ले आया है। अब राज्य सरकार को यह बताना होगा कि उसके द्वारा बनाए गए कठोर दंडात्मक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नागरिकों को प्राप्त धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और राज्य की भूमिका के बीच किस प्रकार संतुलन स्थापित करते हैं।

## बिहार में नई सरकार के बाद प्रशासनिक हलचल तेज, बड़ी संख्या में IAS अफसरों का तबादला, जिलों में जिम्मेदारियों की नई बुनियाद रखी गई

**(जीएनएस)**। पटना। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक ढांचे में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने देर रात 30 से अधिक आईएएस अधिकारियों के तबादले संबंधी अधिसूचना जारी की, जिससे राज्य का नौकरशाही तंत्र एक बार फिर नए समीकरणों के अनुसार ढलने लगा है। जिलों के विकास कार्यों की रफ्तार, कानून-व्यवस्था और नई सरकार की प्राथमिकताओं को जमीन पर उतारने के लिहाज़ से यह अब तक का सबसे व्यापक कसावट अभियान माना जा रहा है।

सबसे बड़ा बदलाव कई जिलों के प्रमुख पदों पर हुआ है। औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को बेगूसराय भेजा गया है, जो औद्योगिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। मधेपुरा के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को पश्चिम चंपारण की जिम्मेदारी मिली है, जहां सीमाई इलाकों की विशिष्ट चुनौतियाँ और प्रशासनिक सतर्कता की उच्च जरूरत होती है। शिवहर के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को सिवान भेजकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पश्चिम बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से सुदृढ़ करना उसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। अरवल की जिलाधिकारी

अभिलाशा शर्मा को अब औरंगाबाद की कमान सौंपी गई है, जिससे वहां हाल के महीनों में तेज़ हुए विकास कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का जिलाधिकारी बनाया गया है। आपदा प्रबंधन और परिवहन विभाग में विशेष कार्य की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल चुके द्विवेदी अब सीमांचल के इस महत्वपूर्ण जिले में नई ऊर्जा के साथ कार्यभार संभालेंगे। बिहार एड्स नियंत्रण समिति की परियोजना निदेशक प्रतिमा रानी को शिवहर भेजा गया है, जिससे छोटे जिलों में प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व सुनिश्चित करने की कोशिश साफ दिखती है। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण का जिलाधिकारी बनाए जाने को एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सारण एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील जिला है, और श्रीवास्तव से सरकार को बेहतर प्रशासनिक तालमेल और विकास की गति की उम्मीद है। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दुहन को अररिया की कमान दी गई है, जो सीमांचल क्षेत्र की जटिल चुनौतियों वाला जिला है। उधर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मत्स्य निदेशक रहे अभिषेक रंजन अब मधेपुरा के जिलाधिकारी होंगे, जहाँ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में प्रशासनिक हस्तक्षेप की विशेष जरूरत महसूस की जा रही है। उद्योग विभाग की तकनीकी विकास निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा का जिलाधिकारी बनाकर सरकार ने प्रशासनिक नवाचार और कड़ाई दोनों को संतुलित करने का संदेश दिया है। अरवल की नई जिलाधिकारी के रूप में अमृता बैंस को नियुक्त किया गया है। ऊर्जा विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में दक्षता और सख़्ती दोनों दिखा चुकीं बैंस से सरकार को छोटे जिलों में सुशासन को और मजबूत करने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षा की निदेशक रहीं सहिला को बक्सर का जिलाधिकारी बनाया गया है, जहां स्कूली शिक्षा और कानून-व्यवस्था दोनों को सुधारने की चुनौती है। कृषि निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर भेजा गया है, जो कृषि प्रधान जिला है और जहां नई तकनीक व योजनाओं के ज़मीनी क्रियान्वयन की बड़ी जिम्मेदारी होगी।

इन व्यापक तबादलों से साफ है कि सरकार आने वाले महीनों में जिला स्तर पर योजनाओं की रफ्तार और निगरानी को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। यह प्रशासनिक पुनर्संरचना न केवल अधिकारों का पुनर्वितरण है, बल्कि राज्य के विकास एजेंडे पर केन्द्रित एक नई सोच का संकेत भी है, जिसमें प्रत्येक जिले को अधिक जवाबदेही और चुस्त नेतृत्व के साथ काम करने की अपेक्षा की गई है।

## राजस्थान के उद्योगपति अजय मुर्डिया और फिल्ममेकर विक्रम भट्ट विवाद की पूरी कहानी, जानिए कौन हैं मुर्डिया और कैसे पहुंचा मामला गिरफ्तारी तक

**(जीएनएस)**। राजस्थान के प्रतिष्ठित उद्योगपति डॉ. अजय मुर्डिया और बॉलीवुड के जाने-माने निर्देशक विक्रम भट्ट के बीच शुरू हुआ एक फिल्म परियोजना का सपना अब धोखाधड़ी, विवाद और गिरफ्तारी की लंबी कहानी में बदल चुका है। यह मामला न सिर्फ मनोरंजन जगत को हिलाकर रख रहा है, बल्कि बिजनेस कारोबारी हलकों में भी गहरी चर्चा का विषय बन गया है। रविवार को मुंबई और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट को मुंबई के यारी रोड स्थित गंगा भवन अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। उदयपुर पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड के जरिए राजस्थान लाने की कार्रवाई में जुट गई है। यह पूरी घटना एक ऐसे व्यवसायी की शिकायत पर आधारित है, जिसकी पहचान और प्रतिष्ठा राजस्थान में बेहद मजबूत मानी जाती है।

डॉ. अजय मुर्डिया, जो इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, लंबे समय से हेल्थकेयर, शिक्षा और मेडिकल रिसर्च के सेक्टर में सक्रिय हैं। उन्होंने वर्षों में राजस्थान में अस्पतालों, पैरामेडिकल कॉलेजों, शिक्षा संस्थानों और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के जरिए एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया है। उनकी छवि एक सामाजिक उद्यमी और शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति

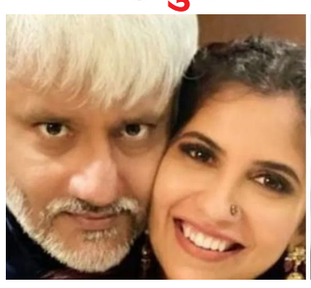

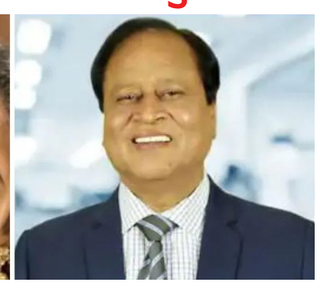

की रही है। लेकिन नवंबर 2024 में उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई, उसने मनोरंजन जगत से लेकर व्यावसायिक दुनिया तक को चौंका दिया।

कहानी की शुरुआत एक कार्यक्रम से हुई थी, जहां अजय मुर्डिया की मुलाकात दिनेश कटारिया नामक व्यक्ति से हुई। कटारिया ने सुझाव दिया कि डॉ. मुर्डिया की पत्नी और उनके जीवन व सामाजिक कार्यों पर एक प्रेरणादायक बायोपिक बनाई जा सकती है। यह विचार मुर्डिया को पसंद आया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके जीवन के संघर्ष और सामाजिक योगदान को फिल्म के माध्यम से देश-भर में पहचान मिल सकती है। इसके बाद बातचीत आगे बढ़ी और उन्हें 24 अप्रैल 2024 को मुंबई के वृंदावन स्टूडियो आने का निमंत्रण मिला।

स्टूडियो पहुंचने पर उनकी मुलाकात फिल्ममेकर विक्रम भट्ट से कराई गई। यहां से शुरू हुई एक नई यात्रा, जिसने आगे चलकर विवाद का रूप ले लिया। कहा गया कि भट्ट दंपति उनकी बायोपिक परियोजना को संभालेंगे और इसके साथ ही दो और फिल्मों—'बायोनिक' और 'महाराणा'—का प्रस्ताव भी उन्हें दिया गया। बातचीत में उन्हें बताया गया कि चार फिल्मों का पैकेज लगभग 40 करोड़ रुपये का होगा और इनसे भविष्य में 100 से 200 करोड़ रुपये तक का मुनाफ़ा भी संभव है। यह आकर्षक प्रस्ताव था, और मुर्डिया ने इस पर सहमति जताई।

31 मई 2024 को मुर्डिया की ओर से 2.5 करोड़ रुपये की पहली किस्त भेजी गई। इसके बाद प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का हवाला देकर 7 करोड़ रुपये की और मांग की गई। मुर्डिया के अनुसार, आगे बढ़ते महीनों में भट्ट दंपति द्वारा बताए गए कई वेंडर्स को भी करोड़ों रुपये का भुगतान कराया गया। इन वेंडर्स के बारे में उन्हें बताया गया कि ये फिल्म निर्माण में आवश्यक उपकरण, तकनीकी सपोर्ट और शूटिंग व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद, जब भुगतान किए गए खातों और व्यक्तियों की जांच शुरू हुई, तो तस्वीर बिल्कुल अलग निकली।

जांच में सामने आया कि जिन वेंडर्स को करोड़ों रुपये भेजे गए, उनमें कई ऐसे लोग शामिल थे जो असल में फिल्म उद्योग से कोई संबंध नहीं रखते थे। कुछ वेंडर्स पुताई मजदूर निकले, तो कुछ ऑटो रिक्शा चालक। इससे शक गहरा हुआ और मुर्डिया ने विस्तृत जांच कराई। दावा है कि करोड़ों की राशि भेजने के बाद उनमें से एक बड़ा हिस्सा श्वेतांबरी भट्ट के खाते में ट्रांसफर होता पाया गया। इससे यह आशंका और मजबूत हो गई कि पूरा प्रोजेक्ट संभवतः एक सुनियोजित धोखाधड़ी की योजना का हिस्सा था।

17 नवंबर को अजय मुर्डिया ने इस पूरे मामले में विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी और कुल आठ व्यक्तियों के खिलाफ 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया। उदयपुर पुलिस ने बीते सप्ताह ही आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था, ताकि वे देश से बाहर न जा सकें। इसी बीच रविवार को पुलिस ने मुंबई में दोनों को गिरफ्तार कर लिया।